सत्यापित शीर्षक क्रमांक
MAH/HIN/50786 /13/1/2013 T.C.

सृष्टी पाक्षिक एग्रो

● वर्ष : 1 ● अंक : 3 ● मुंबई, 1 मार्च से 15 मार्च 2013 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2/- रुपये

जयपुर से दिल्ली; बिजली से दौडेगी ट्रेन

(पृष्ठ ७ पर)

इस साल का बजट किसानों के लिए निराशाजनक

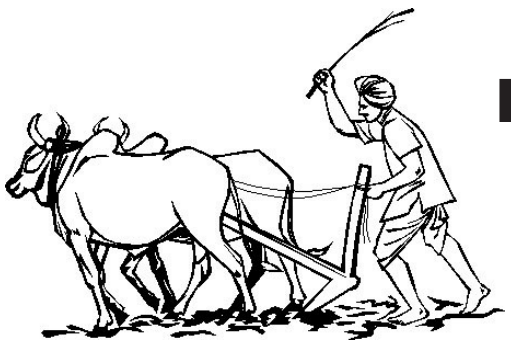

नई दिल्ली -वित्तमंत्री पी चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट २०१३-१४ से किसान काफी नाराज है। बजट में कृषि मंत्रालय को २७०४९ करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो वर्ष २०१२-१३ के संशोधित अनुमान से २२ प्रतिशत अधिक है। इस राशि में से ३४१५ करोड़ रुपए कृषि अनुसंधान के लिए दिये जाने का प्रस्ताव है।

अब कृषि योग्य भूमि की खरीद-फरोख्त पर टीडीएस नहीं देना होगा। ऐसी व्यवस्था की गई है। जिससे किसान निजी बैंक से भी कर्ज ले सकेंगे। छोटे किसानों के लिए जय प्रबंधन के वास्ते बजट में ५,८३७ करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर १०,००० करोड़ रुपये, गांवों की सड़क पर २१,७०० करोड़ रुपये, मनरेगा पर ३३,००० करोड़ रुपए, गांवों के विकास पर ८०,१०० करोड़ रुपए और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर ज्यादा आबंटन कर सरकार ने बता दिया है कि वह आम आदमी के लिए बेहद फिक्रमंद है।

पेश हुए बजट पर देश के प्रमुख किसान संगठन भारतीय किसान युनियन ने कहा कि भारत के वित्तमंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उससे कृषि क्षेत्र को काफी निराशा हुई है। किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बजट ने किसानों को निराशा और कर्ज के सिवा कुछ नहीं दिया गया है। देश की ७० प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र का आवंटन कुल बजट का केवल ३.६ प्रतिशत है। बजट में ४७ प्रतिशत कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि सरकार कृषि को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अन्तर्गत ३६० करोड़ नई फसल प्रोजेक्ट के लिए २००० करोड़ कृषि मंत्रालय को २७००० करोड़ तथा कृषि कर्ज के लिए ७ लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस प्रावधान में अधिकतर रुपया मंत्रालय और योजनाओं के लिए है। किसानों की जीवन सुरक्षा हेतू पेंशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों की मांग थी कि स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को भी लाया जाए। क्योंकि आजकल महंगे इलाज के कारण किसान अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं और मौत की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ इसमें शो भेदभाव करते हुए, रिक्शा चालक, कबाड़ी, ऑटो ड्राइवर को शामिल किया गया है। किसानों के लिए यह निराशाजनक बजट है।

कुष्ठ रोग ग्रसित को २५ किलो गेहूं २ रू. की दर से प्राप्त होगा : जिला रसद अधिकारी

हनुमानगढ़ - जिला रसद अधिकारी अशोक असीजा ने जिले में कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजन एवं कुष्ठ रोग ग्रसित को बीपीएल परिवारों की भांति २५ किलो गेहूं २ रूपये की दर पर वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह सुविधा उन्ही परिवारों को मिलेगी जो पहले से बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, आस्था में शामिल नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को पृथक से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड जारी करवाया जा सकता है।

उन्होने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास उपचार कार्ड नहीं है तो वे जिले के उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) एवं नोडल अधिकारी (कुष्ठ)/जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से तो वह उपचार कार्ड बनाकर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका से राशनकार्ड जारी करवा सकता है। उन्होने बताया कि उक्त राशनकार्ड पर बीपीएल के समान २५ किलो गेहूं २ रू. की दर से प्राप्त होगा।

आलू उत्पादन में बिहार के किसानों का विश्व रिकॉर्ड

पटना - बिहार में नालंदा जिले के सोहडीह गांव के राकेश कुमार ने आलू उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने प्रति हेक्टेयर १,०८८ कुंटल आलू का उत्पादन किया है। अधिकारी इसे आलू उत्पादन का नया विश्व रिकॉर्ड बता रहे हैं। राकेश ने पिछले वर्ष ६६० क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्याज का उत्पादन कर एक रिकॉर्ड बनाया था। आलू उत्पादन में राकेश ने नया रिकॉर्ड अपने ही जिले के एक अन्य किसान के पिछले रिकॉर्ड को तोडकर बनाया है। इससे पहले जिले के देशपुरवा गांव के किसान नीतीश कुमार ने प्रति हेक्टेयर ७२९ कुंटल आलू का उत्पादन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

नालंदा के जिला उद्यान अधिकारी डी एन महतो ने आईएएनएस को बताया कि वैज्ञानिकों के एक दल की निगरानी में प्रति हेक्टेयर १,०८८ कुंटल आलू का उत्पादन किया गया, जो अब तक के सर्वाधिक आलू उत्पादन का विश्व रिकॉर्ड है। उत्पादन के सभी रिपोर्ट राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान सहित कई अन्य संस्थानों को भेजे जा रहे हैं, जहां से विश्व रिकॉर्ड की मान्यता दिलाने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि उपलब्ध आंकडों के मुताबिक इतना उत्पादन कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। नालंदा के जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि जैविक तरीके से खेती कर आलू के उत्पादन में सोहडीह के किसान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। किसानों की मेहनत और सरकारी योजनाओं के लाभ के कारण ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकी है।

एमपी में आठ वर्षों में १०८६१ किसानों ने की आत्महत्या

भोपाल - मध्य प्रदेश में खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए चल रही मुहिम को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकडों ने करारा झटका दिया है। एनसीआरबी के मुताबिक बीते आठ वर्षों में प्रदेश में १०,८६१ किसानों ने खुदकुशी की। इस तरह हर रोज करीब चार किसानों ने मौत को गले लगाया। विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस के विधायक महेंद्र सिंह के एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि राज्य में वर्ष २०११ में १,३२६ किसानों ने खुदकुशी की। इन किसानों की खुदकुशी के कारण अलग-अलग हैं। इनमें से महज १६ किसान ही ऐसे थे, जिन्होंने आर्थिक कारणों से जान दी। गृहमंत्री ने एनसीआरबी के आंकाडों के आधार पर बताया है कि (पृष्ठ ७ पर)

राजकीय सेवा में अच्छा कार्य करने वालों को सदैव याद किया जाता है

झुंझुनू। झुंझुनू जिला कलेक्टर जोगा राम ने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी राजकीय सेवा के दौरान सजग और सतर्क रहकर परायणता, सूझबूझ और ईमानदारी से राजकीय कार्य का समय पर संपादन करता है, उन्हें सदैव याद रखा जाता है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यकुशलता का परिचय नवाचारों के साथ देते हैं वे यहां डॉ. हरसहाय मीणा एवं खेतड़ी के उपखण्ड अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र का यहां से पदोन्नति पर स्थानांतरण होने पर उनके सम्मान समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर ने जिले को राजस्व मामलों के निस्तारण एवं ई-गवर्नेंस में प्रथम स्थान दिलवाने की साथ-साथ जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित करवाने, आईएसओ प्रमाण पत्र दिलवाने और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में त्वरित गति से कार्य करते हुए जो योगदान दिया है, उसे सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नवीन तकनीकीयों को अंगीकार करें और विकट परिस्थतियों में भी कुशलता और सूझबूझ से राजकीय कार्य को परिस्थितयों के अनुरूप निपटाने की सीख भी लेवें। जिला एवं सेशन न्यायधीश महेन्द्र कुमार अग्रवाल, उपखण्ड अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क, पूर्व खेल अधिकारी किशन सिंह, कलेक्ट्रेट कार्यालय अधीक्षक रामधन मीणा, पटवारी उम्मेद सिंह महला ने भी यहां से स्थानांतरित हुए दोनों प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली

की सराहना करते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की । अपर कलेक्टर डॉ. हरसहाय मीणा ने कहा कि उन्होंने सभी के समन्वित सहयोग से जिले को

हर क्षेत्र में प्रथम स्थान दिलवाने का प्रसाय किया है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के मार्गनिर्देशन में ही निचले स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते है। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार एडीएम बनकर झुंझुनू आए तो उन्हें अजीब सा लग रहा था, लेकिन उन्हें यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने बताया कि एक दिन में खाता विभाजन का रिकार्ड भी कायम किया है।

MANUFACTURER AND BULK SUPPLIER OF FERTILIZERS PRODUCTS

UDIT OVERSEAS PVT. LTD.

137, INDUSTRIAL AREA DEHRA, TEHSIL-CHOMU, DISTT. JAIPUR

Products Range:-

Micronutrients
Mixture
Secondary Nutrients
Growth Promoters
Bio Stimulants
Bio Fungicide
Bio Insecticide
Bactericide
Wetting Agent
Zyme
Tonic

WE WELCOME YOUR INQUIRY .....

CONTACT DETAIL

MR. ALOK BENIWAL
MOB: 9660258447

संपादकीय

नए खाद्य तंत्र की जरूरत

आम तौर पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते समय खेती की अनदेखी कर दी जाती है जबकि सच्चाई यह है कि आधुनिक खेती जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बनकर उभरी है। खेत में पैदा होने से लेकर थाली तक की यात्रा में रासायनिक उर्वरक, भारी मशीनरी और तेल आधारित तकनीक के उपयोग की गणना की जाए तो कुल कार्बन उत्सर्जन में खेती का योगदान ५० फीसदी तक पहुंच जाता है। फिर पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, प्रशीतन और लंबी दूरी तय करने के कारण खाद्य पदार्थ न केवल बरबाद होते हैं, बल्कि करोडों लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसे में एक नए खाद्य तंत्र की जरूरत है ताकि जलवायु परिवर्तन व भुखमरी पर लगाम लगाई जा सके। आहार तैयार करने की हर प्रक्रिया में बडे पैमाने पर जीएचजी का उत्सर्जन होता है। खाद्य पदार्थों के परिवहन से छह फीसदी जीएचजी उत्सर्जित होती है। प्रसंस्करण, पैकेजिंग व प्रशीतन में भी बडे पैमाने पर जीएचजी उत्सर्जित होती है। फिर खाद्य पदार्थों के उत्पादन व उपभोग में गहरी खाई विद्यमान है।

औद्योगिक खाद्य तंत्र में पैदा होने से लेकर सुपर मार्केट में पहुंचने तक आधे खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते है। इन्हें कचराघरों में डंप करने व उनके सडने से भी बडी मात्रा में जीएचजी उत्सर्जित होती है। यह नष्ट खाद्य सामग्री दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों से छह गुना अधिक लोगों के पेट की आग शांत कर सकती है। स्पष्ट है जब तक हम मौजूदा खाद्य तंत्र से नहीं निकलेंगे तब तक जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर होगी। इसकी शुरुआत मिट्टी से करनी होगी। यूरोप और अमेरिका में शुरू हुई और बाद में हरित क्रांति के रूप में तीसरी दुनिया में प्रचलित हुई औद्योगिक खेती में मिट्टी की उर्वरता में कमी की भरपाई रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से की जाने लगी। इस प्रक्रिया में मिट्टी में पाए जाने वाले जैविक तत्वों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि २०वीं शताब्दी में मिट्टी के ३०-७५ फीसदी जैविक तत्व नष्ट हो गए। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आई बल्कि बाढ व सूखे की समस्या भी गंभीर हुई। इनमें से सभी जैविक तत्व कार्बन डाइआक्साइड के रूप में वायुमंडल में नहीं मिल गए बल्कि एक बडी मात्रा नदियों, झीलों व समुद्र की तलहटी में जमा हुई। यह अनुमान है मिट्टी के जैविक तत्वों के विनाश में वायुमंडल में २००-३०० अरब टन कार्बन डाइआक्साइड जमा हुई। दूसरे शब्दों में आज वायुमंडल में जो कार्बन की अधिकता है उसका २५ से ४० फीसदी मिट्टी के जैविक तत्वों के नष्ट होने से जमा हुई है। यदि हम दोबारा प्राकृतिक तरीके से खेती करने लगें तो एक बार फिर वायुमंडलीय कार्बन डाइआक्साटइड मिट्टी में जमा होने लगेगी।

दुनिया भर के किसान दशकों से इस पद्धति से खेती करते रहे हैं जैसे विविध फसलों की मिश्रित खेती। इसे अपनाने से मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा धीरे-धीरे बढेगी जिससे मिट्टी की उर्वरता, जल ग्रहण क्षमता व नमी में वृद्धि होगी जिसका परिणाम उत्पादकता में बढोतरी के रूप में सामने आएगा। फिर मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा बढने से फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढेगी और वे कीटपतंगों और मौसमी उतार-चढाव को आसानी से झेल लेंगी। खेती की पद्धति में बदलाव के साथ ही हमें खाद्य तंत्र से जुडे जीएचजी उत्सर्जन के अन्य पक्षों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले छोटा व स्थानीय बाजार आधारित खाद्य वितरण तंत्र की स्थापना की जाए। इससे खाद्य पदार्थों के परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग व प्रशीतन का खर्च बचेगा। दूसरे, फसल उत्पादन व पशुपालन का एकीकरण हो ताकि उर्वरकों के प्रयोग में कमी आए। तीसरे, जैव ईंधन और पशु आहार के लिए एकफसली खेती के विस्तार पर रोक लगे ताकि निर्वनीकरण की गति कम हो सके। यदि दुनिया उपर्युक्त चार सुधारों को गंभीरतापूर्वक लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाए तो जीएचजी उत्सर्जन में कटौती के लिए सम्मेलनों, प्रस्तावों की जरूरत नहीं रह जाएगी।

खेती में नई तकनीक का फायदा लें – कृषि वैज्ञानिक

झुंझुनू। कृषि विज्ञान केन्द्र, झुंझुनू में जिला स्तरीय किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने खेती पर विचार व्यक्त किये। करीब चार हजार किसानों से भरे पाण्डाल में कृषि वैज्ञानिकों ने खेती पर सवाल जवाब कर अपनाई जा रही नई तकनीक के बारे में किसानों से पूछा। किसान मेले के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख हनुमान प्रसाद थे। किसान मेले की अध्यक्षता कर रहे स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विष्वविद्यालय बीकानेर के निदेशक (प्रसार शिक्षा) डॉ. पी.एन. कल्ला ने कहा जब तक किसान नई तकनीक से खेती नहीं करेंगे उन्हें घाटा होगा।

किसानों को नई तकनीक अपनाकर खेती से बेहतर लाभ कमाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर के क्षेत्रीय निदेशक डा. सहदेव सिंह ने विभिन्न फसलों में लगने वाले रोगों एवं उनके रोकथाम के उपाय बताए। जिला परिशद सी.ई.ओ. रामनिवास जाट ने कहा कि नई तकनीक से भी खेती में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उपनिदेशक कृशि विस्तार डूंगाराम जाट दुर्गापुरा, जयपुर ने जल संग्रहण के बारे में जानकारी दी। उपनिदेशक कृषि शंकरराम बेड़ा ने स्वागत भाषण व विभागीय प्रतिवेदन पेश किया। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक सुभाष गोदारा, कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एस.एम. मेहता, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. डूडी ने भी विचार व्यक्त किये। संचालन कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. राकेश डूडी व पी.टी.आई सत्यवीर झाझड़िया ने किया। इस अवसर पर सहायक निदेशक कमलेश कुल्हरी, चिड़ावा के डॉ. राजेन्द्र लांबा कृषि अधिकारी शीशराम जाखड़, डॉ. प्रमोद यादव, रोहिताष्व, आत्मा के उप परियोजना निदेशक विजयपाल कस्वां आदि मौजूद थे। किसान मेले में विभिन्न कृषि आदान निर्माता कम्पनीयों ने भी अपनी स्टॉल लगाकर उत्पादों का प्रदर्शन किया। जिनमें हिन्दकेम कॉरपोरेशन, मुम्बई, पायोनियर सीड्स एवं चम्बल फर्टिलाइजर्स प्रमुख थे।

हिन्दकेम कॉपोरेशन के शेरसिंह स्टाल पर किसानों को जानकारी देते हुए।

ओलावृष्टि से फसलें चौपट, किसानों द्वारा मुआवजे की माँग

जयपुर। प्रदेश में गत दिनों हुई भारी ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में रबी की फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। हाड़ौती में कई स्थान पर नींबू के आकार के ओले पड़ने से यहां धनिया एवं लहसुन की फसलों में किसानों को भारी नुकसान होने की सूचना है। वहीं मारवाड़ क्षेत्र में भी ओलावृष्टि से ईसबगोल, जीरा व प्याज की फसल में नुकसान की खबर है। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से आंकल न करने को कहा।

अनूपगढ़। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा मांग का एसडीएम को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि ओला प्राकृतिक आपदा है। सरकार को सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए। दुग्गल ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर माकपा के सभी विधायक विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरेंगे और किसानों को मुआवजा दिलवाकर रहेंगे। जिला परिशद सदस्य सुनील गोदारा ने कहा कि क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है।

करौली। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अलका मीणा ने मंडरायल क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान का जायजा और पीड़ित किसानों को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने बताया कि जिलाध्यक्ष ने मंडरायल तहसील के घटली, फिरोजपुर, धौरेटा, जाखोदा, तुलसीपुरा, गोपाल पुरा, आदि गांवों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। किसानों ने सहकारिता विभाग से लिए ऋणों को माफ करने, बिजली बिलों को माफ करने व खराब फसल का मुआवजे की मांग की। उन्होंने कलेक्टर व तहसीलदार से वार्ता कर किसानों की मांगों से अवगत कराया और किसानों को आश्वासन दिया कि वह सरकार से उन्हें उचित मुआवजा दिलाएंगी।

झालावाड़। जिले में ओलावृष्टि व बारिश से हुए फसलों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। खानपुर व बकानी में प्रदर्शन किया गया। वहीं कई अन्य इलाकों में किसानों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। खानपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर विधायक की अगुवाई में किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसी भी अधिकारों के नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने बारां-झालावाड़ मेगा हाइवे पर जाम लगा दिया। धरने में विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित मुआवजा नुकसान के आगे कुछ भी नहीं है। इसे किसानों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा -ओला

झुंझुनू। आपदा प्रबंधन एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने कहा है कि हाल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीतलहर और पाले को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल कर लिया है, जिसके फलस्वरूप अब किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने यह जानकारी यहां सांख्यिकी भवन के उद्घाटन समारोह में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टर को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों के चार माह के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे और सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली निरस्त करते हुए उन्हें मध्यकालीन ऋणों में बदला जाएगा।

सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही योजनाओं का निर्धारण होता है -ओला

झुंझुनू। सैनिक कल्याण मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने कहा है कि देश व प्रदेश की सभी योजनाएं सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही बनती हैं और जनसंख्या के आधार पर ही योजना आयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए योजनाओं का निर्धारण करता है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के आधार पर ही देश और प्रदेश के विकास का आंकलन किया जाता है। वे यहां जिला मुख्यालय पर बनाए गए नए सांख्यिकी भवन का लोकार्पण करने के बाद समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि शहर के विकास में एक नया आयाम स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सांख्यिकी भवनों का पंचायत समिति मुख्यालयों तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने एनएसएस के आंकड़ों को विश्वसनीय बताते हुए कहा कि अगर जनसंख्या के आंकडे. सही फीड होंगे, तो आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्धारण भी सही होगा। उन्होंने कार्मिकों से कहा कि वे कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखें। उन्होंने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर जोगा राम के निर्देशन में शहर के विकास को गति मिली है और प्रशासन द्वारा भूमि आंवटन करने के फलस्वरूप ही सरकार द्वारा सैनिक भर्ती कार्यालय का भवन भी बनवाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान में जिले को अग्रणी स्थान प्राप्त होने पर धन्यवाद किया।

जिला कलेक्टर जोगा राम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलग से अपने भवन में बैठकर कार्य करने का जो अवसर मिला है, उससे कार्य की गुणवत्ता में निखार आएगा और समय पर सभी आंकड़े सुगमता से भिजवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जनगणना का कार्य करवाया गया है, जबकि वर्तमान में आर्थिक स्वास्थ्य सूचकांक का सर्वे चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की रीतियों और नितियां भी आंकड़ों पर ही निर्भर करती है। समारोह के अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख डॉ. हनुमान प्रसाद ने कहा कि समय के साथ विकास को गति अवश्य मिलती है और योजनाओं का आधार सांख्यिकी सूचनाएं ही होती है। पंचवर्शीय योजनाओं में आंकड़ों का विशेष महत्व होता है। नगर परिषद के सभापति खालिद हुसैन ने भी शहर विकास में प्रशासन द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने शहर विकास का संकल्प दोहराया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भवन के लिए भी अलग से भूमि आवंटन करने की मांग की।

प्रारम्भ में सांख्यिकी अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि इसी भवन के निर्माण पर लाखों रूपयों की लागत आई है और भविश्य में जिले के पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी विभाग के कार्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं। उन्होंने विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा हर पांच वर्श बाद जनगणना का कार्य किया जाता है और जन्म-मृत्यु के आंकड़ों का संकलन हर माह किया जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं फसल कटाई अनुमान आंकलन तथा विभिन्न वस्तुओं के बाजार भाव आंकलन की भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रारम्भ में विभागीय अधिकारियों द्वारा सैनिक कल्याण राज्य मंत्रे सहित जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, सभापति, उपसभापति श्रीमती बिमला बेनीवाल और पंचायत समिति प्रधान सुशीला सिगड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। न्यू राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्याल य की छात्रओं द्वारा स्वागत गायन प्रस्तुत किया गया। अंत में विभाग के वशिष्ठ शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीशाशी अभियन्ता पूरण सिंह, सहायक ढाका, जिला परिशद की निशा चौधरी, महेन्द्र झाझडिया, पूर्व पार्शद रामनारायण कुमावत सहित अन्य विभागीय अधिकारी, मीडियाकर्मी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मूलचंद झाझड़िया ने किया।

सहकारिता से ही खाद्य संकट दूर होगा

संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कहा है। ऐसे में, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र का मूल विषय कृषि सहकारिता- विश्व को भोजन देने की कुंजी उचित ही है। इसमें कोई शक नहीं कि खाद्यान्न के मोर्चे पर हम कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जोत के आकार का निरंतर घटते जाना। इसलिए भी जो मूल रूप से खेती-किसानी पर निर्भर परिवार हैं, जिनकी तादाद देश में लगभग १२ करोड है। ये छोटे और सीमांत किसानों के परिवार हैं। खेती-किसानी का चक्र लागत, जोखिम और नफा के आसपास घूमता है। यही खेतों में किसानों की निवेश क्षमता को निर्धारित करता है।

जमीन के छोटे रकबे को हम दूसरे नजरिये से भी देख सकते हैं। यह एक मौका भी मुहैया कराता है कि हम अपने खेती-तंत्र को गहन और विविधतापूर्ण बनाएं। लेकिन यह भी सच है कि छोटे किसानों को कई तरह की कठिनाइयों से गुजरना पडता है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी आकार के मामले में भले ही छोटी हैं, पर संसाधनों के खर्च के मामले में कतई किफायती नहीं हैं। इन बाधाओं को पार करके हम छोटे किसानों को खेती के छोटे रकबे से मुनाफा दिला सकते हैं, जो कि पर्यावरण के भी उपयुक्त है। ऐसे में, भारतीय कृषि के सामने बडी समस्या है कि छोटे उत्पादकों को ऊर्जा व पूंजी मिले और इन्हें प्रदान करने के तरीकों का मानकीकरण हो। दुग्ध उद्योग के साथ जो हमारे अनुभव हैं, वे बताते हैं कि अगर आम लोग उत्पादन से जुडें और उस उत्पादन को सही तरीके से एकीकृत किया जाए, तो छोटे उद्योग को किसी सहारे की जरूरत नहीं पडती। दूसरे शब्दों में, अगर केंद्रीकृत सेवाओं द्वारा समर्थन हो, तो छोटे उत्पादन तंत्र को विकेंद्रीकृत ही रखना चाहिए। इससे छोटे किसानों को उत्पादन बढाने में मदद मिलती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। इसी वजह से आज हम दुनिया में सबसे बडे दुग्ध उत्पादक हैं। इसके लिए दूध के प्रसंस्करण और विपणन, दोनों को धन्यवाद। साथ ही दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाएं, जैसे गुजरात की अमूल कॉपरेटिव को भी शुक्रिया। अगर सहकारी संस्थाएं सफल न होतीं, तब हम प्रबुद्ध स्वार्थ के सिद्धांत पर सहयोग को बढावा दे सकते थे। खेती-किसानी की दूसरी बडी समस्या यह है कि युवा पीढी इससे विमुख होती जा रही है। इस पीढी के कई लोग खेती की जमीन को दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ साल पहले भारत सरकार ने खेती-किसानी के क्षेत्र में स्नातक किए लोगों को एग्रीक्लीनिक्स और कृषि-व्यापार केंद्रों से जुडने के कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन इसे लेकर युवाओं में उत्साह नहीं दिखा। ऐसे में यही वह वक्त है, जब नाकामी से सबक लेते हुए इसे फिर से खडा किया जाए। आदर्शत: चार से पांच कृषि स्नातक का एक समूह, जो खेती-किसानी, पशु पालन, मत्स्य पालन, कृषि-कारोबार और गृह विज्ञान में विशेषज्ञ हों, प्रत्येक ब्लॉक में संयुक्त रूप से एग्री-क्लीनिक-कम-एग्री-बिजनेस सेंटर खोल सकते हैं। एग्री-क्लीनिक खाद्य-उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी सेवा देगी और एग्री-बिजनेस फसल कटाई के बाद खेतीहर परिवारों की दिक्कतें दूर करेंगी। इस तरह से खेतीहर लोगों को पूरे फसल-चक्र तक, बुआई से लेकर फसल-कटाई और विपणन तक, मदद मिलेगी। कृषि के विविध विषयों के जानकार युवा उद्यमियों का यह समूह कृषक परिवारों को मदद पहुंचाएगा। गृह विज्ञान विशेषज्ञ खेती-किसानी से जुडी महिलाओं या खेतीहर परिवारों की महिलाओं के साथ मिलकर फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का दल इन परिवारों को ऊर्जा और पूंजी की उपलब्धता के आधार पर खेती के सुझाव देंगे और उनके लिए ऊर्जा के स्त्रोत भी ढूंढेंगे। इस एकीकृत केंद्र को 'कृषि परिवर्तन केंद्र' कहा जा सकता है। युवा उद्यमियों के लिए कई अवसर हैं। जलवायु के मुताबिक खेती एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सूखे इलाकों में वर्षा जंल संचयन व भंडारण, नदी, सरोवर, तालाब में पानी पुनर्भरण और जल प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, मिट्टी के भौतिकी, रसायन व सूक्ष्म जीव विज्ञान पर भी काम करने की जरूरत है। वैसे पेड लगाने ही होंगे, जिनसे जमीन उर्वर हो और मिट्टी में कार्बन सोखने की क्षमता बढे। ग्रीन इंडिया मिशन और मनरेगा के तहत इसे मुमकिन किया जा सकता है। साथ ही अगर हर खेत के लिए जल कुंड और बायोगैस संयंत्र हों, तो क्या कहने। इससे निश्चित तौर पर सूखेग्रस्त इलाकों में उत्पादन और लाभ, दोनों में जबरदस्त बढोतरी होगी। ये वैसे उपाय हैं, जिनसे जलवायु परिवर्तन में भी कमी आएगी। महिला स्वयं-सेवी संस्थाओं को जैविक खाद, जैव कीटनाशक और वर्मिकल्चर बनाने व उन्हें बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसमें हमारे युवा किसान भी मदद करेंगे। उन जैविक सॉफ्टवेयर को भी बनाया जा सकता है, जो टिकाऊ खेती के लिए उपयोगी होते हैं। स्नातक छात्र स्थानीय तकनीकों व कम लागत के जरिये भी समुद्र व नदी-तालाबों में मत्स्य पालन को बढावा दे सकते हैं। यही नहीं, इससे जुडे कारोबार को स्थानीय स्तर पर बढावा भी दिया जा सकता है। पशुपालन के क्षेत्र में भी समान अवसर मौजूद हैं। छोटे स्तर पर बेहतर तकनीकों के साथ मुर्गी पालन और दुग्ध उत्पादन को बढाने की जरूरत है। खाद्य उत्पादन के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा भी आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, हम भारतीय इस ओर कम ही ध्यान देते हैं। इसके लिए युवा किसानों को चाहिए कि वह ज्ञान चौपाल केंद्रों की स्थापना करें। इन केंद्रों पर इंटरनेट, एफएम रेडियो और मोबाइल-टेलीफोन की सुविधाएं होनी चाहिए। वक्त-वक्त पर जमीन और पानी की जांच भी जरूरी है। युवा किसान घूम-घूमकर जमीन और पानी की जांच का कार्यक्रम चला सकते हैं। और इस आधार पर फार्म पासबुक भी जारी किया जा सकता है। फार्म पासबुक में मिट्टी की सेहत, जमीन की गुणवत्ता और फसल व जानवरों की बीमारियों के बारे में जानकारी होगी। खेती के उत्थान के लिए किसान चाहें, तो जलवायु जोखिम प्रबंधन केंद्र भी चालू कर सकते हैं, जिनसे बेहतर मानसून का अधिकतम फायदा होगा और खराब मौसम संबंधी दिक्कतें कम से कम होंगी। शिक्षित युवा किसान सूचनाओं का फायदा उठाएं, तो यह सबके लिए फायदेमंद है। दरअसल, आज की खेती काफी हद तक इकोटेक्नोलॉजी पर निर्भर है, यानी पारंपरिक ज्ञान और बेहतर प्रौद्योगिकी दोनों ही। खेती के सतत विकास को आगे बढाने और खाद्य सुरक्षा में आगे इसकी अहम भूमिका रहेगी, बशर्ते शिक्षित युवा गांव से किनारा न कसें और नए कृषि आंदोलन में बढ-चढकर हिस्सा लें। अगर यह मुमकिन हुआ, तो वह दिन दूर नहीं कि जिस विशाल आबादी के भरण-पोषण के लिए हम खाद्य संकट का रोना रोते हैं, वहीं आबादी खेती की तस्वीर बदल देगी। अपना पेट तो भरेगी ही, दूसरे देशों के खाद्य संकट को भी दूर करेगी।

- एम एस स्वामीनाथन, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक

किसकी जेब में कृषि ऋण?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने खुलासा किया है कि किसानों की कर्ज माफी योजना में बडे पैमाने पर गडबडियां हुई हैं। यह योजना वर्ष २००९ के आम बजट में आम चुनावों से पहले लागू की गई थी। ७४,००० करोड रूपए के कर्ज माफ किए जाने थे। कर्ज माफी योजना को लेकर काफी उत्सुकता थी। पर योजना के आंतरिक प्रावधानों से प्रभावशाली लोगों को ही फायदा मिला। मोटे तौर पर योजना से आठ-दस प्रतिशत किसान ही लाभान्वित हुए। इसका सीधा अर्थ यही निकला कि ३५.५ लाख किसानों को कर्ज माफी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। इसके अलावा से अयोग्य किसानों की बडी संख्या थी, जिन्हें अदायगी से छूट मिल गई और उन्होंने ऋण का भुगतान नहीं किया।

यह रहस्योद्घाटन से समय हुआ है, जब कृषि ऋणों में लाभार्थियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लाभ किसे मिला? हर साल के बजट में कृषि ऋण आवंटन की राशि बढाई जाती रही है। २०१२-१३ के बजट में ५,७५,००० करोड रूपए का कृषि ऋण देने का बजटीय प्रावधान किया गया था। एक साल पहले २०११-१२ के बजट में ४,७५,००० करोड रूपए निर्धारित किए गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, वर्ष २००० और २०१० के बीच कृषि ऋण ७५५ प्रतिशत तक बढा है। इस साल अपेक्षित है कि वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम नए बजट में कृषि ऋणों के लिए आवंटन और बढाएंगे, इसे ७,००,००० करोड रूपए तक कर देंगे। इससे लगता है कि यदि छोटे व सीमांत किसानों को कृषि ऋणों के जरिए इतनी बडी राशि दी जा रही है, तो कृषि मोर्चे पर सब कुछ ठीकठाक होगा।

लेकिन ऋण वितरण की हकीकत वास्तविकता से परे है। खेती के मोर्चे पर कृषि संकट का गहराना जारी है। कृषि ऋणों के लिए जो आवंटन बढाया जाता है, उसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। पिछले पन्द्रह वर्षों में २.९० लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अन्य लगभग ४२ प्रतिशत किसान, यदि उन्हें आय का और कोई जरिया मिल जाए, तो वे खेती-किसानी छोडने के लिए तैयार बैठे हैं। बढता कृषि संकट ऋण के विशाल आवंटन से मेल नहीं खाता है। हमने बार-बार सुना है, कृषि ऋण उत्पादन बढाने और किसानों की तकलीफ दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। योजना आयोग के १२वीं पंचवर्षीय योजना(२०१२-२०१७) के दस्तावेज में भी कृषि विकास के लिए कृषि ऋण बढाने की बात कही गई है।

यह बात तब कही गई है, जब एसोचैम की 'फार्म क्रेडिट' रिपोर्ट मे पिछले दशक में बांटे गए कृषि ऋणों के दुरूपयोग का विश्लेषण किया गया है। देखने में आया है कि बडे खेतों के मालिक अनुपात में तो कम ब्याज पर ज्यादा कृषि ऋण ले लेते हैं, और फिर वह पैसा अन्य आकर्षक योजनाओं, क्षेत्रों में लगा देते हैं, जिससे उन्हें अधिक फायदा होता है। जो छोटे-गरीब किसान हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा पाते।

यदि आप एसोचैम की रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति को देखें तो साफ पता चल जाएगा कि संस्थागत ऋण योजना अपनी पहुंच बनाने में कहां विफल हुई है। छोटे और सीमांत किसानों सहित खेती से जुडा लगभग अस्सी प्रतिशत कृषि कार्यबल सा है, जिन तक सरकार अपनी पहुंच बनाने में सफल नहीं हो सकी है, उन्हें अपनी योजनाओं से लाभान्वित नहीं कर सकी है और जिन्हें वाकई में ज्यादा जरूरत है? रिजर्व बैंक साफ दिखने वाली इस असमानता पर मूकदर्शक कैसे बना हुआ है? क्या इतने वर्षों में उसे सच्चाई नहीं दिखनी चाहिए थी? क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है?

एक खबर के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में कृषि ऋण की राशि ढाई गुना तक बढाई गई, लेकिन पूरे संस्थागत ऋण मे से ६ प्रतिशत से भी कम हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध कराया जा सका। विडम्बना है, सत्तारूढ दल में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री समेत अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक पूरी फौज है, जो छोटे और सीमांत किसानों तक ऋण पहुंचने की बात कहते थकती नहीं है। न पहुंच पाने को लेकर तनाव महसूस नहीं करती है।

वर्ष २००७ में बैंकों द्वारा २,२९,४०० करोड रूपए के ऋण दिए गए थे। इसमें छोटे किसानों का हिस्सा मात्र ३.७७ प्रतिशत ही था। दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो ९६.२३ प्रतिशत कृषि ऋण का वितरण बडे किसानों या कृषि व्यापार में लगी कम्पनियों को किया गया। वर्ष २०११-१२ में कृषि ऋण बांटने का लक्ष्य ५,०९,००० करोड रूपए तक बढाया गया, पर केवल ५.७१ प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सके। यह जानते हुए भी कि गडबडी है, सरकार छोटे और सीमांत किसानों के नाम पर कृषि व्यापार से जुडी कंपनियों का समर्थन करती रही है। १९९३ में कृषि ऋण की व्याख्या विशद की गई थी, इसमें कृषि व्यापार कम्पनियों, कृषि उपकरण बनाने वाले निर्माताओं, वेयरहाउस को भी शामिल किया गया। से ही अन्य लोग हैं, जो ४ प्रतिशत ब्याज दर का लाभ उठा लेते हैं। यह झटके देने वाला रहस्योद्घाटन है कि ७४,००० करोड रूपए का जो कृषि ऋण माफ किया गया था, उसका एक बडा हिस्सा लक्षित जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया। यह महत्वपूर्ण है, पी. चिदम्बरम अपने बजट भाषण २०१३ में यह स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में कितना ऋण कृषि क्षेत्र के लिए है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। किसानों के नाम पर व्यावसायिक उपक्रमों को ४ प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर ऋण देने में कोई आर्थिक बुद्धिमानी नहीं है। किसानों के नाम पर वितीय संसाधनों को कारपोरेट्स की ओर चतुराई पूर्वक खींचने का काम अवश्य बंद होना चाहिए।

यही वह प्राथमिक कारण है, जिसके चलते छोटे और सीमांत किसान अपने हाल पर छोड दिए गए हैं। उनके पास उन सूदखोर ऋणदाताओं पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो बेहिसाब सूद वसूलते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, किसानों द्वारा आत्महत्या का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। इसका संस्थागत ऋण के अभाव से बडा सरोकार है। - देविन्दर शर्मा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ

सरकार की लैपटॉप खरीद योजना विवादों में

जयपुर- मेरिट में आने वाले छात्रों को लैपटॉप देने की राजस्थान सरकार की योजना विवादों में आ गई है। योजना के पहले चरण में १,१२ लाख लैपटॉप खरीदने के टेंडर में एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तो में बदलाव किया गया। भाजपा ने लैपटॉप खरीद में बडे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टेंडर शर्तो में बदलाव की जांच की मांग की है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने लैपटॉप खरीद के टेंडर में ऐसी शर्ते डाल दी जिससे सॉ३टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट और हार्डवेयर में इंटेल को छोड बाकी सभी कंपनियां बाहर हो गई। लैपटॉप खरीद के लिए जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ ओपन सोर्स लाइनेक्स भी मांगा गया था। अब टेंडर शर्ते बदलकर केवल माइक्रोसॉफ्ट कर दिया है। इस शर्त से अब केवल माइक्रोसॉफ्ट ही बिडिंग कर सकेगा।

टेंडर में एंटी वायरस सॉ३टवेयर केवल माइक्रोसॉफ्ट का मांगा गया है। जबकि कई और कंपनियां भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप हार्डवेयर की शर्तो में भी बदलाव किया गया। पहले प्रोसेसर किसी भी कंपनी का मान्य था, नई शर्तो में केवल इंटेल का ही प्रोसेसर मांगा है। इस पूरे टेंडर में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल को फायदा पहुंचाने के लिए शर्ते बदली गई।

टेंडर के तकनीकी मांग पत्र में एमएस विंडोज ७, ऑफिस २०१० और एंटी वायरस में भी केवल माइक्रोसॉफ्ट के ही उत्पाद मांगे हैं। जबकि ओपन सोर्स में ये सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध है। पहले एमएस विंडोज के साथ ओपन सोर्स लाइनेक्स भी मांगा गया था लेकिन बाद में हटा दिया। एसी एडॉप्टर और चार्जर वोल्टेज रेंज ११० वॉल्ट से २५० वॉल्ट मांगा गया है। जबकि भारत में अधिकतम वोल्टेज २४० वॉल्ट से ज्यादा नहीं है। नई वोल्टेज रेंज का चार्टर मांगना यही साबित करता है कि केवल एक कंपनी इस रेंज के एडॉप्टर और चार्टर बनाती है। इसे फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है।

प्रदेश सरकार आईटी सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है कि आज ९० प्रतिशत लोग माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं। ओपन सोर्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक साथ काम नहीं कर सकते। लैपटॉप में लाइनेक्स सॉ३टवेयर से बच्चों को कठिनाई होती। प्रोसेसर के लिए हमने इंटेल और एमडी दोनों कंपनियों को मौका दिया है। ये दो ही अच्छी कंपनियां हैं। हमने बच्चों का फायदा देखते हुए ही सारी शर्ते तय की हैं, तकनीकी रूप से सब सही है।

कार्बन डाईआक्साइड के उच्च स्तर से गेहूं को फायदा

सिडनी। जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में बढता कार्बन डाई आक्साइड का स्तर वास्तव में सूखाग्रस्त इलाकों में गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद हो सकता है। आस्ट्रेलिया में हुए एक शोध में इसका खुलासा हुआ है।

वेस्टर्न आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में शोध छात्र एडुआडरे डायस डी ओलीविएरा ने अपनी तरह के दुनिया के पहले शोध में पाया कि गेहूं को कार्बन डाईआक्साइड के सीधे संपर्क में लाने पर अत्यधिक गर्म वातावरण तथा पानी की कमी से जूझने की उसमें ताकत आ जाती है।

ओलीविएरा की इस खोज से आस्ट्रेलिया के भूमध्यरेखीय इलाकों के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में फसल उत्पादन के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड सकता है।

विश्वविद्यालय में प्रवक्ता तथा शोध के सहलेखक कदम्बोत सिद्दीकी ने बताया कि वातावरणीय तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने तक फसलों के विकास में तेजी ही आई भले उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दिया गया।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए योजना बनी

जयपुर। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वर्ष २००६ में आई थी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुस्लिमों के बीच साक्षरता दर काफी गिरती जा रही है। इस पर गौर करते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक योजना बनाई है। राजस्थान सरकार ने अल्पसं२यक मामलों पर एक अलग विभाग का गठन किया है जो अल्पसंख्यक समूहों, खासकर युवाओं व महिलाओं के संगठनों के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अल्पसंख्यक समुदाय की मांग पर मुख्यमंत्री ने इस समुदाय से सम्बंधित विभिन्न कल्याण योजनाओं और विभागों को एक ही विभाग के अंतर्गत लाने की पहल की है।" अधिकारी ने कहा, 'उनके कल्याण की दिशा में अगला कदम उठाते हुए इस समुदाय के युवाओं को बेहतर शक्षिक सुविधाएं देकर तथा वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण सवाओं में सुधार लाकर उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है।' उल्लेखनीय है कि राज्य की कुल आबादी ६ करोड ८६२ लाख है जिनमें लगभग आठ फीसदी मुस्लिम हैं।

बारिश की मार की वजह से किडनी बेचने को मजबूर किसान

गुंटूर: आंध्र प्रदेश के गुंटूर के किसान अप्पा राव के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उसने अपनी किडनी बेच दी। ३० साल के इस किसान

करीब एक साल पहले अपनी किडनी बेची थी। उसे तब दलाल द्वारा कहा गया था कि किडनी के लिए साढे चार लाख रुपये दिए जाएंगे। अप्पा को दलाल तमाम कागजात दिखाए और बताया कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हो रही है। उन कागजातों में तमाम सरकारी अधिकारियों और डॉक्टरों के दस्तखत थे। इन पूरे कागजातों में यह कहा गया कि अप्पा राव ने अपनी किडनी अपनी मर्जी से पाने वाले के प्रति लगाव की वजह से दान में दी है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अप्पा राव को मात्र एक तिहाई रकम ही दी गई।

अपनी किडनी को 'बेच' देने के निर्णय का कारण बताते हुए अप्पा राव ने कहा कि २००९ में बारिश की वजह से उनकी फसल पूरी तरह बरबाद हो गई। फिर छोटा कारोबार करने के लिए अप्पा ने बाजार में निजी व्यवसायी से ऊंचे ब्याज पर पैसा लिया था। ब्याज की वजह से मासिक शुल्क बहुत ज्यादा हो गया था। इसके बाद जैसे ही किडनी बेचने का प्रस्ताव अप्पा नकार नहीं पाए। जब अप्पा ने इस बारे में अपने घर में चर्चा की तब उसकी बीवी और मां ने ऐसा कुछ भी करने मना कर दिया लेकिन मैंने कहा कि अब आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं रह गया है।

अप्पा ने कहा, दलाल ने धोखा दिया और करीब दो लाख से ज्यादा रुपया नहीं दिया। लेकिन मैं अब किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। अब मेरी सेहत खराब हो चुकी है। काम नहीं कर सकता। मुझे अपना गांव छोडना पडा है और नाम छुपाकर रहना पड रहा है। बता दें कि आंध्र के गुंटूर में तमाम किसान मिर्च और कपास की खेती करते हैं। सूखा, तूफान और गैर-मौसमी बारिश ने उनकी फसल को चौपट कर दिया है। स्थानीय लोगों को अप्पा राव की कहानी से ज्यादा फर्क नहीं पडता है। पलानाडू इलाके के भी तमाम किसानों की भी लगभग यही कहानी है। हालात अब यह हो गए हैं कि कुछ अब खुद ही दलाली का काम करने लगे हैं। इन मामलों का कागजात बताते हैं कि किडनी निकालने की सर्जरी हैदराबाद के बडे अस्पतालों में की गई है और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए। तमाम किडनी बेचने वाले अपना नाम तक बताने को राजी नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे खुद कानूनी पचडे में फंस जाएंगे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन मामलों में कार्रवाई करके भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कोर्ट में कागजात पर सब निर्भर करता है। अभी तक इन मामलों में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है।

राज्य के मानवाधिकार आयोग ने अब सरकार को लिखा है कि मामले की पूरी जांच कर वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट दें। आयोग ने पूछा है कि आखिर कैसे इस तरह मानव अंगों के प्रत्यर्पण का गैर-कानूनी काम चल रहा है। अप्रैल के अंत तक इस रिपोर्ट के आने की संभावना है।

HINDCHEM CORPORATION

Wholesale supplier of Fertilizers & Pesticides throughout the nation.

Contact Person: **Mr. Alpesh Mathur** Mob: 09829220788

PLOT NO. B-81-82, NEELGIRI COLONY, BEHIND NEW ANAJ MANDI, OPPOSITE ROAD NO. 9, VKI AREA, JAIPUR-302013 PH: 0141-3130277

रेल ट्रैक पर बैठे किसान ब्रिगेड के सदस्य

जींद : किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिए जाने तथा सरकार और किसानों के बीच से बिचौलियों को समाप्त किए जाने की मांगों को लेकर जींद में कई दिन से आंदोलन कर रहे किसान ब्रिगेड के सदस्यों ने बरसोला गांव के पास दिल्ली-भटिंडा रेलवे सैक्शन पर रेल ट्रैक पर आकर कुछ देर के लिए धरना दिया।

इन लोगों का मकसद यहां किसी तरह से ट्रेन रोकने का था लेकिन मौके पर पहले से ही तैनात पुलिस बल और जी.आर.पी. तथा जींद प्रशासन के अधिकारियों ने इन लोगों को रेल ट्रैक से हटाकर इनके रेल रोकने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान यहां कई दर्जन कार्यकत्ताओं को राजकीय रेलवे पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अखिल भारतीय किसान ब्रिगेड के अध्यक्ष संदीप चौधरी अपने साथियों के साथ जींद में पिछले महीने से जींद में लघु सचिवालय परिसर के बाहर धरने और अनशन का कार्यक्रम चलाए हुए थे। कई दिनों तक इनके अनशन के बाद भी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने इन लोगों से बात नहीं की थी। कुछ दिन पहले इस संगठन ने जींद की जाट धर्मशाला में महापंचायत बुलाकर आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया था। इस आंदोलन के तहत अखिल भारतीय किसान ब्रिगेड के अध्यक्ष संदीप चौधरी की अगुवाई में ब्रिगेड के ७० से ज्यादा कार्यकत्ता सोमवार सुबह ही जींद के बरसोला गांव मंर दिल्ली-भड्क्षठडा रेलवे सैक्शन पर पहुंच गए थे।

इन लोगों ने रेल ट्रैक को कब्जाने का ऐलान किया हुआ था। इसे देखते हुए सोमवार को बरसोला के पास भारी संर२या में जिला पुलिस और जी.आर.पी. के जवान तथा पुलिस और प्रशासन के बडे अधिकारी भी बरसोला पहुंच गए थे। बरसोला के रेलवे ट्रैक को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। खुद जींद के डी.सी. एम.एल. कौशिक तथा एस.पी. बलवान सिंह राणा भी बरसोला के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। मौके पर जींद के एस.डी.एम. दलबीर सिंह तथा डी.एस.पी. अमरीक सिंह भारी पुलिस बल के साथ तैनात थे। सोमवार दोपहर बाद किसान ब्रिगेड के कार्यकत्ताओं ने महज धरना देने की खातिर रेल ट्रैक पर बैठने की बात कही और यह लोग ट्रैक पर बैठ गए। उस समय तक पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी कि किसान ब्रिगेड के सदस्यों का मकसद यहां धरना देकर रेल गाडी को रोकने का है। दोपहर बाद जब एक गाडी इस ट्रैक पर आने लगी तो पुलिस प्रशासन ने रेल ट्रैक पर बैठे किसान ब्रिगेड के अध्यक्ष संदीप चौधरी समेत उनके तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तुरंत प्रभाव से हिरासत में लेते हुए रेल ट्रैक को खाली करवा दिया।

राजस्थान के लिये उम्मीद की किरण हैं वसुंधरा राजे

क्या् आपको लगता है अलवर में शाहजहांपुर से जयपुर तक १५० किलोमीटर की दूरी तय करने में १२ घंटे लगेंगे? किसी से पूछिये या अनुमान लगाने पर ज्यादा से ज्या दा साढे तीन घंटे कहेगा, लेकिन जब वसुंधरा राजे ने यह यात्रा की, तो उन्हें १२ घंटे क्यों लगे। ऐसा ही त्योलहार जैसा मंजर था ८ फरवरी को जब वसुंधरा राजे इस मार्ग पर चलीं। हजारों लोग वसुंधरा राजे की एक झलक पाने को बेताब दिखे। वृद्ध, युव, हिन्दू, मुस्लिम, सर्वण वर्ग, व निचली जाति, सभी एक ही महिला को देखना चाहते थे। यह मंजर सिर्फ अलवर से जयपुर का नहीं बल्कि पूरा राजस्थान अब वसुंधरा को ही अगले मुख्यअमंत्री के रूप में देखना चाहता है। पिछले चार-पांच साल वसुंधरा राजे के लिये आसान नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लोगों की दुआएं और प्यार मिला तो उन्हें आगे बढने से अब कोई नहीं रोक सकता है। राजे इस समय न केवल भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, बल्कि पार्टी का चेहरा भी हैं, जो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और २०१४ में होने वाले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। खास बात यह है कि इस शो की सिर्फ एक स्टार होंगी और वो हैं वसुंधरा!

वसुंधरा ही क्यों ? आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजस्था न की राजनीति में निर्णायक भूमिका वसुंधरा कैसे निभा सकती हैं? चुनाव के दौरान उनके बिना भाजपा को मुश्किलों का सामना क्यों करना पड सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब हैं– क्योंकि आंकडे ऐसा कह रहे हैं अगर आप आंकडों पर ध्या न दें तो सभी संरयाक वसुंधरा राजे के पक्ष में दिखेंगी। उन्हीं के नेतृत्वड में २००३ में राजस्था न में भाजपा की सर्वश्रेष्ठ जीत हुई थी। उस समय भाजपा को २०० में से १२० सीटें मिली थीं यानी ४० फीसदी।

पिछले तीन दशकों में भाजपा ने दो बार सरकार बनायी लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। लेकिन २००३ में वसुंधरा राजे के हाथ में कमान सौंपे जाने के बाद भाजपा को व्यापिक स्त र पर बढत हासिल हुई। देखा जाये तो २००३ में भाजपा का सर्वोत्त म प्रदर्शन रहा। इस समय राजे और उनकी टीम विपक्ष में है। क्योंकि भ्रष्टातचार में डूबी हुई है अशोक गहलोत की सरकार यदि वर्तमान कांग्रेस सरकार पर नजर डालें तो राज्य सरकार गले तक भ्रष्टाकचार में डूबी हुई है। अप्रैल २०११ से आयीं तमाम खबरों में राजस्था न सरकार को बेनकाब किया गया। ११ हजार करोड के घोटाले मं गहलोत के परिवार तक के शामिल होने की बात आयी। उनके परिवार के सदस्यल मुंबई में रियल इस्टेकट के कारोबार को आगे बढाने में राजनीतिक सपोर्ट ले रहे हैं। खुद गहलोत ने अपने भाई–बंधुओं की कंपनियों के हित में कई निर्णय लिये। यहां तक राजस्था न में कोई भी इंफ्रास्ट्रिक्चबर से संबंधित सौदा हो, जब तक गहलोत के परिवार का हस्तथक्षेप नहीं हो, तब तक पास नहीं होता। जब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाडरा के कारोबार से जुडीं खबरें आयीं तो एक बात उठी कि उनके बिजनेस में किसी राज्या सरकार ने भारी फायदा पहुंचाया है। वो राजस्थाउन सरकार ही थी। वाडरा को मुनाफा पहुंचाने में गहलोत प्रशासन ने भूमि से लेकर जमीर तक सब बेच डाला, सिर्फ पैसा कमाने और १० जनपथ में वफादारी पेश करने के लिये। इस दौरान वसुंधरा राजे ने लोगों के सामने गहलोत सरकार को बेनकाब करने का एक भी अवसर नहीं छोडा। जनता को अब इस बात का अहसास हो गया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश को एक दशक पीछे धकेल चुकी है, लिहाजा गहलोत सरकार को सबक सिखाना चाहती है। ३. समाज का कोई तबका, महिलाएं या अल्पतसंरयसक राजस्था न में सुरक्षित महसूस नहीं करता है आज राजस्थाोन में समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं है, जो खुद को सुरक्षित महसूस करता हो। चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष। हर व्यहक्ति इस समय नाखुश है। सिक्केत के दूसरी ओर देखें तो कोई ऐसा समाज नहीं है, जहां वसुंधरा राजे का नाम प्ररयात नहीं हो। चाहे गांव के किसान हों, या फिर शहर के बिजनेसमैन सभी से एक जैसा व्यंवहार। वो वृद्ध किसान से भी उतनी ही अच्छीर तरह बात करती हैं, जितनी अच्छीा तरह एक युवती से। राजे ने महिलाओं, दलितों और अल्पबसंरय कों के साथ एक गहरा नाता जोड लिया है। यह महत्वनपूर्ण है, क्योंयकि दलित और मुसलमान पहले भाजपा के समर्थक कम ही हुआ करते थे। भंवरी देवी कांड के बाद से महिलाओं का विश्वासस वर्तमान सरकार के ऊपर से उठ चुका है। सामाजिक मुद्दों पर बात करने के बजाये राजस्थारन सरकार महिलाप मदेरणा और मल्खाजन सिंह बिश्नोलई को बचाने में जुटी हुई है। दोनों ही नेताओं के कांग्रेस के साथ मजबूत संबंध हैं। कहानी पूरी तरह बदल जाती है, जब वसुंधरा राजे की बात आती है, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं। और उस नाते वो महिलाओं के दर्द को समझती हैं और जब वो सत्तोि में थीं, तब महिलाओं के उत्थांन के लिये कई कार्य हुए थे। भंवरी देवी का मामला उजागर होने पर वसुंधरा ही थीं, जिन्होंने दोनों नेताओं को हटाने की मांग की। आज जब वो राज्यर में कहीं जाती हैं, तो भारी संरयां में महिलाएं उन्हें सुनने आती हैं। ये महिलाएं खुद को राजे के समक्ष सुरक्षित महसूस करती हैं। कांग्रेस दावा करती है कि वो मुसलमानों का खास खयाल रखती है, लेकिन गोपालगढ, भरतपुर में मुसलमानों पर पुलिस का अत्याचार क्यास था। यहां पर पुलिस की बर्बरता की पोल खोनले वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक जाहिदा खान ही थीं। यहां तक राष्ट्री य मॉयनॉरिटी कमीशन ने इस मामले के लिये राज्यक सरकार को ही जिद्मे दार ठीराया था। हाल ही में एक सर्वे हुआ, जिसमें पाया गया कि मुस्लिम वोटर गहलोत सरकार से नाखुश हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं। वो मानते हैं कि वसुंधरा के शासन में वो ज्या दा सुरक्षित थे। यह बात गौर करने वाली है। जहां तक युवाओं की बात है, तो नौकरियों की कमी, जन–विरोधी नीतियां और बढती महंगाई के कारण युवाओं और गहलोत के बीच गहरी खायी बना दी है। इसका ट्रेलर छात्रसंघ चुनाव में देखने को मिल ही गया, जहां कांग्रेस की एनएसयूआई को हर तरफ हार झेलनी पडी। तब तो और जब स्कू ली छात्राओं ने सुविधाओं के अभाव की बात कही। राज्य के युवा अब वसुंधरा राजे की ओर देख रहे हैं। उन्हेंव उधर अवसर दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के एक छात्र ने मुझे बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो शिक्षा के लिये लिया गया लोन उनके माता–पिता के लिये चुकाना कठिन होगा। भाजपा के शासन में सबकुछ अलग था। मुझे लगता है कि ऐसा बाकी छात्र भी जरूर सोचते होंगे।

क्योंकि सरकार स्वगर्ण शून्यथ तक पहुंच गई है थोडा बहुत भ्रष्टालचार माफ किया जा सकता है, लेकिन भारी भरकम भ्रष्टाणचार और शासन के नाम पर कुछ नहीं, इसे माफ करना बहुत कठिन हे। यह बात राजस्थाान का एक लेबर कहता है। राजस्थांन सरकार को कोसने वाला यह लेबर कहता है, 'देखिये गुजरात की तरक्की देखिये, वह स्वार्ण युग की ओर अग्रसर है और पडोसी राज्यय राजस्थाकन में क्या, है, शून्या। हमारे परिवार के कई सदस्यु अब गुजरात भाग रहे हैं।' इसके अलावा गहलोत के शासन में राजस्थाईन की जीडीबी गिर कर ५.४ प्रतिशत होना। साफ दर्शाता है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ई–गवर्नेन्स. के मामले में भी सरकार बहुत पीछे है। क्याक ऐसी सरकार दोबारा आनी चाहिये? पश्चिम बंगाल में ले३ट का पतन हो गया, अब ममता बनर्जी प्रदेश को तेजी से आगे ले जा रही हैं। गुजरात में नरेंद्र मोरी का करिश्मार ऐसा है, जिससे अमेरिका तक वाकिफ हो चुका है। महाराष्ट्रा में कांग्रेस–एनसीपी और उत्तर प्रदेश में सपा। दुर्भाग्य वश राजस्थामन इन मामलों में फेल साबित हो रहा है। गहलोत और उनकी टीम की सिर्फ एक विचारधारा है वो है भ्रष्टोचार और आलाकमान के लिये वफादारी। यहां तक अब कांग्रेस के विधायक भी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस समय राजस्था।न के लोग अंधेरे में जी रहे हैं और उद्मीतद की एक किरण दिखाई दे रही है। वो किरण जो उन्हेंध विकास और समृद्धि की ओर ले जायेगी, जहां पुलिस की गोलियां बेकसूर लोगों को नहीं लगेंगी, जहां महिलाएं आत्मजसद्मा न के साथ जियेंगी और सुरक्षित रहेंगी, जहां अवसर बनेंगे और वो हैं वसुंधरा राजे। अब आप ही बताइये गहलोत की सरकार दोबारा आनी चाहिये?

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना-२०१२

संस्था प्रधानों को समीक्षा बैठक में दिये आवश्यक निर्देश

कोटा - उच्च शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस वर्ष प्रथम वर्ष में प्रवेशित प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना-२०१२ से लाभान्वित किया जायेगा। यह जानकारी सोमवार को यहां टैगोर हॉल में आयोजित योजना संबंधी समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कल क्टर (सीलिंग) श्रीमती आराधना सक्सेना ने की।

बैठक में श्रीमती सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं में शामिल है और राज्य सरकार द्वारा इसकी समयबद्ध क्रियान्विती सुनिश्चित की जा रही है। योजना का लाभ सरकारी एवं निजी कॉलेजों के उन विद्यार्थियों को देय होगा, जिन्होंने वर्ष २०१२ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी संकाय में ६० प्रतिशत या अधिक प्राप्तांकों से १२ वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और वर्तमान में किसी महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत है।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) ने बताया कि योजनान्तर्गत किसी भी महाविद्यालय, इंजीनियरिंग, पोलीटेक्निक, नर्सिंग, आयुर्वेद, संस्कृत शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथाम वर्ष के नियमित छात्र/छात्रा पात्र माने गये हैं। ऐसे विद्यार्थी राजस्थान के मूल निवासी हों तथा उनके परिवार की वार्षिक आमदनी ढाई लाख या इससे कम होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि देश एवं राज्य से किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि ले रहे विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने की संशोधित तिथि २८ फरवरी हो गई है। विद्यार्थियों को आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय में ही जमा करवाने हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की १२ वीं की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति, स्वयं द्वारा उद्घोषित शपथ पत्र पर दिया गया आय प्रमाण पत्र, राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की प्रति, शुल्क जमा की रसीद की मूल प्रति, एस.बी.बी.जे.बैंक खाते की पासबुक की प्रमाणित प्रति तथा अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने का १० रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आदि दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी महाविद्यालय में एक भी पात्र विद्यार्थी इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिये। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के नॉडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य हैं जिन्हें सभी महाविद्याल यों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने हैं। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता में महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा संस्था प्रधानों की सक्रिय सहभागिता एवं पूर्ण सहयोग मिलना जरूरी है। बैठक में योजना के नॉडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो० सुनील भार्गव ने भी योजना की जानकारी दी। बैठक में मोदी कॉल ेज के प्राचार्य डॉ० एल.के.दाधीच तथा अन्य संस्था प्रधानों ने अपने विचार व्यक्त किये।

डांग क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए २७ लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी

कोटा . डांग क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष २०१२-१३ में पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर की ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यों के लिए २७ लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सी.पवन ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति इटावा के ग्राम खेडा में मेन रोड स्कूल से कीरों की बस्ती की ओर सीसी रोड मय नाली निर्माण के लिए २.५० लाख रूपये, गैंता में राजीव गांधी भवन से मेन रास्ते तक सीसी रोड निर्माण के लिए ३ लाख रूपये, नलावता में सीसी रोड निर्माण मय नाली निर्माण के लिए २.५० लाख रूपये, कैथूदा में खरंजा निर्माण के लिए १.५० लाख रूपये, दुर्जनपुरा में राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चारदीवारी के लिए २.५० लाख रूपये, खेडली में सीसी रोड मय नाली निर्माण के लिए १.२५ लाख रूपये, नोनेरा में सीसी रोड के लिए १.२५ लाख रूपये, खेडली महाराज में सीसी रोड मय नाली निर्माण के लिए २.५० लाख रूपये एवं गुवाडी गांव में खरंजा निर्माण मय पुलिया के लिए २ लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सुल्तानपुर के ग्राम बिसलाई में खरंजा निर्माण के लिए ३ लाख रूपये, मोहम्मदपुरा में सीसी रोड के लिए २ लाख रूपये तथा टाकरवाडा में सीसी रोड निर्माण के लिए ३ लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

फाइनल टच दे रहे हैं राहुल गांधी

नई दिल्ली। बजट सत्र के पहले दिन जहां राष्ट्र पति प्रणब मुखर्जी ने यूपीए की जमकर सराहना कर अपना काम पूरा कर दिया। उन्हों ने यूपीए के तुरुप के पत्तों को रणभूमि में बिछा दिया। अब बारी है चाल को आगे बढाने की, तो उसके लिये राहुल गांधी ने कमर कस ली है। जी हां कांग्रेस उपाध्यनक्ष ने गुरुवार को संकेत दिया कि वर्ष २०१४ के आम चुनाव के लिए पार्टी की टीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किए जाने के बाद राहुल ने संवाददाताओं से कहा, 'पार्टी में प्रतिभाओं की भरमार है..यह देखकर मैं बहुत उत्साहित हूं..सिर्फ उन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत है।' राहुल संसद के केंद्रीय कक्ष में आखिरी दूसरी पंक्ति में बैठे थे। रक्षा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और गृह राज्यमंत्री आर.पी.एन. सिंह भी उनकी बगल में बैठे थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल अपने मोबाइल फोन का कई बार उपयोग करते देखे गए।

पिछले महीने कांग्रेस उपाध्यक्ष बने राहुल यह जानने के लिए कि पार्टी कहां-कहां मजबूत और कहां-कहां कमजोर है, इधर कुछ हफ्तों में पार्टी पदाधिकारियों, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश इकाइयों के प्रमुखों और विधायक दल के नेताओं से लगातार मिलते रहे हैं। राहुल गांधी के त्व रित दौरे सीधा संकेत दे रहे हैं कि जल्दस ही वो अपनी टीम की घोषणा कर देंगे। राहुल वर्ष २०१४ के आम चुनाव के लिए गठित समन्वय समिति के प्रमुख भी हैं। संभावना है कि वह युवा नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। हम आपको बता दें जिस टीम की सोनिया गांधी ने घोषणा की थी, वो चुनाव के कार्यों को वृहद स्त र पर काम करने के लिये बनायी गई है, उसी टीम में राहुल गांधी अन्यद युवा नेताओं को भी शामिल करना चाहते हैं, जो जमीनी स्तवर पर काम करेंगे।

ओलावृष्टि एवं शीतलहर से फसल को नुकसान की विस्तृत गिरदावरी कराई जाएगी -अशोक गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने ओला वृष्टि एवं शीतलहर से प्रदेश में फसल को हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत गिरदावरी करवाने का निर्णय लिया है। गहलोत शून्यकाल में इस संबंध में हुई चर्चा के दौरान हस्तक्षेप कर रहे थे। गहलोत ने बताया कि ओलावृष्टि एवं शीतलहर से फसल को हुए नुकसान के बारे में अब तक जो रिपोर्ट आई है और जनप्रतिनिधि की ओर से जो सूचना दी गई है उसमें भारी अंतर है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टरों, उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों से व्यापक गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि गिरदावरी की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ओलावृष्टि एवं शीतलहर से हुए नुकसान के संबंध में राहत पहुंचाने के बारे में जो भी निर्णय लेगी उसकी जानकारी पहले राज्य विधानसभा को दी जाएगी तथा इसमें जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि से नुकसान के संबंध में राज्य सरकार एक पैकेज पहले ही दे चुकी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि काष्तकारों को कृषि आदान अनुदान के संबंध में लिया गया फैसला खरीफ की फसल के संबंध में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि आदान अनुदान का पैसा पहले से ही राज्य सरकार के पास उपलब्ध था और हम चाहते हैं कि मानदण्डों के अनुसार ही किसानों की मदद की जा सके।

जयपुर से दिल्ली; बिजली से दौडेगी ट्रेन

जयपुर। रेल मंत्रालय अब ज्यादा से ज्यादा रेल लाइनों के विद्युतीकरण पर काम कर रहा है। इसकी शुरूआत दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद रेललाइन से हो सकती है। सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड और वित्त मंत्रालय की हरी झंडी के बाद गुरूवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भी इस रेललाइन के विद्युतीकरण की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इसे बजट में शामिल किया जा सकता है।

दिल्ली सराय रोहिल्ला से रेवाडी-अलवर-बांदीकुई-जयपुरफुलेरा-पालनपुर-अहमदाबाद होते हुए गांधीनगर तक विद्युतीकरण किया जाएगा। अप और डाउन दोनों ट्रैक (२०९४ किमी) के विद्युतीकरण पर ११२२ करोड रूपए खर्च होने का अनुमान है। बजट में इसे मंजूरी मिल जाने पर यह कार्य २०१८ तक पूरा किया जा सकता है।

हर साल बचेंगे ५२२ करोड : एक वरिष्ठ अभियंता के अनुसार हर वर्ष करीब ५२२ करोड रूपए के एक लाख १५ हजार लीटर हाईस्पीड डीजल की बचत होगी। इससे उत्तर रेलवे-उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के कई शहरों को लाभ होगा। आपात स्थिति में और गाडियों के बढने पर इसका बेहतर प्रयोग किया जा सकेगा।

एमपी में आठ वर्षों में १०८६१ किसानों ने की आत्महत्या

(पृष्ठ १ से)२००४- २०११ के दौरान स्वरोजगार के लिए कृषि कार्यो से जुडे १०,८६१ लोगों ने जान दी। एनसीआरबी के आंकडों के मुताबिक वर्ष २००४ में १६३८, २००५ में १२४८, २००६ में १३७५, २००७ में १२६३, २००८ में १३७९, २००९ में १३९५, २०१० में १२३७ और २०११ में १३२६ किसानों ने खुदकुशी की। बीते आठ सालों के खुदकुशी के आंकडों पर गौर करें तो पता चलता है कि हर रोज ३७१ किसानों ने अपनी जीवन लिला समाप्त की। दूसरे शब्दों में हर छह घंटे में एक किसान ने मौत को गले लगाया। सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि कि कृषि कार्य से जुडे लोगों ने पारिवारिक विवाद, नशे की लत, बीमारी, आर्थिक व अन्य कारणों से खुदकुशी की।

आलू के प्रमुख रोग एवं उनके प्रबंधन

आलू सब्जियों की मु२य फसल है इसकी खेती भारत मे प्रमुख फसल के रूप से ली जाती है परन्तु रोगों के कारण इसकी खेती प्रभावीत हो रही हैं किसानो को ६०-७० प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड रहा है इस तरह के नुकसान से बचने के लिए की किसानों को आलू के प्रमुख रोगों एवं उनके उचित प्रबंधन की जानकारी आवश्यक है इस लेख का प्रमुख उद्देश्य किसानों को आलू के प्रमुख रोगों के लक्षणों कि जानकारी देना हैं ताकी वे उसे पहचान कर उस रोग का उचित प्रबंधन कर सकें।

अगेती अंगमारी या अर्ली ब्लाइट

यह रोंग फफूंद की वजह से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण नीचे की पत्तियों पर हल्के भरे रंग के छोटे- छोटे पूरी तरह बिखरे हुए धब्बों से होता हैं। जो अनुकूल मौसम पाकर पत्तियों पर फैलने लगते है। जिससे पत्तियॉ नष्ट हो जाती है। इस बिमारी के लक्षण आलू मे भी दिखते हैं भूरे रंग के धब्बें जो बाद मे फैंल जाते हैं जिससे आलू खाने योग्य नही रहता है।

प्रबंधनः-

- बुवाई से पूर्व खेत की सफाई कर पौधों के अवशेशो को एकत्र कर जला देना चाहिए।
- आलू के कंदो को एगेलाल के ०.१ प्रतिशत घोल में २ मिंनट तक डुबाकर उपचारित करके बोना चाहिए।
- रोग प्रतिरोधक जाति जैसे कुफरी जीवन, कुफरी सिंदूरी आदि।
- फाइटोलान, ब्लिटाक्स- ५० का ०.३ प्रतिशत १२ से १५ दिन के अन्तराल में ३ बार छिडकाव करना चाहिए।

पछेती अंगमारी रोंग

यह रोंग फफूंद की वजह से होता है। रोग के लक्षण सबसे पहले निचे की पत्तियों पर हल्कें हरे रंग के धब्बें दिखई देतें है जो जल्द ही भूरे रंग के हो जाते हैं। यह धब्बें अनियमित आकार के बनते

हैं। जो अनुकूल मौसम पाकर बडी तीव्रता से फैलते हैं और पत्तियों को नश्ट कर देतें है। रोग की विशेश पहचान पत्तियों के किनारें और चोटी भाग का भूरा होकर झुलस जाना हैं। इस रोग के लक्षण कंदो पर भी दिखइ पडता है। जिससे उनका विगलन होने लगता हैं।

प्रबंधनः-

- बुवाई के पूर्व खोद के लिकाले गए रोगी कंदो को जलाकर नश्ट कर देना चाहिए।
- प्रमाणीत बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- रोग प्रतिरोधी जातीयों का चयन किया जाना चाहिए जैसे कुफरी अंलकार, कुफरी खासी गोरी, कुफरी ज्योती, आदि।
- बोर्डो मिश्रण ४:४:५०, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का ०.३ प्रतिशत का छिडकाव १२-१५ दिन के अन्तराल मे तीन बार किया जाना चाहिए।

भूरा विगलन रोग एवं जीवाणु म्लानी रोग

यह जिवाणु जनित रोग हैं। रोग ग्रसित पौधे सामान्य पौधो से बौने होते है। जो कुछ ही समय मे हरे के हरे ही मुरझा जाते है। प्रभावित पौधों की जडो को काटकर कॉच के गिलास मे साफ पानी में रखने से जीवाणु रिसाव स्पश्ट देखा जा सकता हैं। अगर इन पौधो मे कंद बनता है तो काटने पर एक भूरा धेरा देखा जा सकता हैं।

प्रबंधनः-

- गृष्मिकालिन गहरी जुताई किया जाना चाहिए।
- प्रमाणीत बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- बुवाई के पूर्व खोद के लिकाले गए रोगी कंदो को जलाकर नश्ट कर देना चाहिए।
- कंद लगाते समय ४-५ किलो ग्राम प्रति एकड की दर से ब्लीचिंग पाउडर उर्वरक के साथ कुंड मे मिलायें।
- रोग दिखई देने पर अमोनियम सल्फेट के रूप मे देना चाहिए जो रोग जनक पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।

काला मस्सा रोग

यह रोंग फफूंद की वजह से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण पौधो कंदो पर पर दिखाई पडता हैं। जिसमे भूरे से काले रंग के मस्सो की तरह उभार दिखाई देते है जिससे कंद खाने योग्य नही रह जाता हैं।

प्रबंधनः-

- प्रमाणीत बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- बुवाई के पूर्व खोद के लिकाले गए रोगी कंदो को जलाकर नश्ट कर देना चाहिए।
- प्रतिरोधक जातियो का प्रयोग किया जाना चाहिए।

समान्य स्कैब या स्कैब रोग

रोंग फफूंद की वजह से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण पौधो कंदो पर पर दिखाई पडता हैं। कंदो मे हल्के भूरे रंग के दिखई फोडे के समान स्केब पडते है जो की कुछ उभरे और कुछ गहरे स्केब दिखई पडते है जिसके कारण कंद खने योग्य नही रह जाते।

प्रबंधनः-

- प्रमाणीत बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- बुवाई के पूर्व खोद के लिकाले गए रोगी कंदो को जलाकर नश्ट कर देना चाहिए।
- बीज को आरगेनोमरक्यूरीयल जैसे इमेशान या एगालाल धोल के ०.२५ प्रतिशत धोल मे ५ मिनट तक उपचारीत करें।

U S AGROCHEM PVT. LTD.

Wholesale supplier of :

- Fertilizers
- Bio Stimulants
- Micronutrients Mixture
- Single Nutrients

Contact Person:
Mr. AJAY KHANDELWAL
Mob: 09829227491

PLOT NO. B-82, NEELGIRI COLONY, BEHIND NEW ANAJ MANDI,
OPPOSITE ROAD NO. 9, VKI AREA, JAIPUR-302013 PH: 0141-3130277
EMAIL: usagrochem_jaipur@yahoo.com

एसबीसी गैस उपभोक्ताओं को मिलेंगे डीबीसी गैस कनेक्शन

गैस कनेक्शनधारकों को नहीं मिलेगा केरोसीन

भरतपुर - जिले के सभी एसबीसी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को डीबीसी गैस कनेक्शन में परिवर्तित किया जायेगा।

जिला कलेक्टर जीपी शुक्ला ने जिले की सभी गैस ऐजेन्सियों को निर्देश दिये हैं कि जो भी उपभोक्ता अपने एसबीसी गैस कनेक्शन को डीबीसी गैस कनेक्शन में परिवर्तित कराने के लिये आवेदन करें तो उसे यथाशीघ्र डीबीसी गैस कनेक्शन में परिवर्तित करें। उन्होंने कहा है कि यदि कोई ऐजेन्सी डीबीसी गैस कनेक्शन में आनाकानी करे अथवा गैस कनेक्शन के साथ अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री लेने हेतु बाध्य करे तो ऐसे प्रकरणों में जिला रसद अधिकारी द्वारा संबंधित गैस ऐजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने जिले में स्थित सभी उचित मूल्य दुकानदारों को भी निर्देशित किया है कि वे सूचना पट्ट पर इस आश्य की सूचना आवश्यक रूप से अंकित करें कि " सभी एसबीसी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि आगामी १ मार्च २०१३ से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन नहीं दिया जायेगा अतः ऐसे सभी उपभोक्ता अपने से संबंधित गैस ऐजेन्सी पर एसबीसी से डीबीसी गैस कनेक्शन में परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर मार्च माह से पूर्व डीबीसी गैस कनेक्शन में आवश्यक रूप से परिवर्तित करा लें। इसी प्रकार "एसबीसी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता को १ मार्च २०१३ से केरोसीन देय नहीं होगा" आश्य की मोहर प्रत्येक एसबीसी गैस कनेक्शनधारी केरोसीन उपभोक्ता के राशन कार्ड पर लगाना उचित मूल्य दुकानदार सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार १ मार्च २०१३ से केवल बिना गैस कनेक्शनधारी शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक समान मात्राा तीन लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड प्रति माह दिया जायेगा जबकि एसबीसी एवं डीबीसी गैस उपभोक्ताओं को केरोसीन देय नहीं होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटींग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगाव, पूर्व, मुंबई- 62 से मुद्रीत किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड, मालाड, पश्चिम, मुंबई- 400064 यहाँ से प्रकाशित किया। संपादक- सुरेश जी. शर्मा। **CONTACT DETAIL** • TEL : 022-66998360 / 61 • FAX : 022-66450908 • Email : srushtiagro_india@yahoo.com • Webside : srushtiagro.com)